

रांची, शुक्रवार
03.05.2024

वर्ष : 9, अंक : 151 पृष्ठ : 12
मूल्य : दो रुपए

बिहान भारत

रांची से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

खबरे हमारी, विश्वास आपका



राहुल गांधी पर पीएम नोटी ने साधा निशाना

शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला

छंगेंसी

हेमंत सोरेन सहित अन्य आरोपितों की न्यायिक हियासत अवधि बढ़ाई गई

रांची। बड़गाँड़ अंचल की जमीन घोटाले मामले के आरोपित जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, निर्वाचित उप राजस्वकर्मी भानु प्रताप प्रसाद और फर्जी दस्तावेज तेवर करने के मास्टरमाइड मोहम्मद सहाम की पेशी विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से ईडी के विशेष नायाचारी राजीव रंजन की अवधि में हुई। युवराज को कोर्ट ने तीनों की न्यायिक हियासत की अवधि 16 मई तक के लिए बढ़ा दी है। मामले में अगली पेशी 16 मई को होगी। मामले को लेकर ईडी ने ईमीआईआर 6/2023 दर्ज किया है। मामले में भानु प्रताप प्रसाद, हेमंत सोरेन पहिले पांच के खिलाफ ईडी आरोप सहित जाव कर दिया कर चुकी है। ईडी ने डेर्मेंट सोरेन को 31 जनवरी की रात गिरपत्र किया गया था। मामले में ईडी ने अपसर अली, अंतु तिकी, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इशाक को भी गिरफतार कर रिमांड पर छुटकारा के बाद जेल भेज दिया है।

कांग्रेस उम्मीदवार यथार्थिवानी छह को करेंगी नामांकन

रांची। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार यथार्थिवानी सहाय छह मई की अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद भीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पार्टी विधायक दल नेता अलामगीर अलाम, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और कई मंत्री और विधायक शामिल होंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत की क्रिनिल रीट पर ऐसला आज

रांची। झारखण्ड हाई कोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफतारी के खिलाफ दावर याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफतारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हेमंत सोरेन का कहना था कि उके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है, वह मनी लाइंड्रिंग का नहीं है, जिसके लिए उनके नामके नामांकन की बात ईडी कह रहा है। अदेश सुरक्षित रखने के बाद फैसला नहीं सुनाए जाने के लिए उम्मीदवारों की चाही रही है।

रांची। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार यथार्थिवानी

रहे चौथरी फैसला हुसैन ने कांग्रेस को आयात करने के लिए ज़ूझ रहा है। जिन हाथों में बम होते थे, वे अब भीख का कटोरा पकड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हाना, निराश है और हार मान चुके हैं। गांधी ने एक्स पर एक पोर्ट में कहा है कि इन चुनावों में हार के लिए अब तक रहे हैं और भारत दुनिया का सबसे तेजी से उभरता देश है और उसे विश्व बृहुत के तौर पर देखा जाता है जो दो देशों के बीच विवादों को हल कर सकता है। आरक्षण के मुद्दे पर उहाँने अरोप लगाया, कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, जो कि प्रधानमंत्री ने कहा वे बृहुत बैंक है। इसके लिए वे संविधान में बदलाव चाहते हैं। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूँ कि वह लिखित में दे कि वह मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और ईडी याचिका पर आरक्षण देना चाहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की मोदी का बयान ऐसे समय में आया है। उहाँने कहा, एक दिन पहले पाकिस्तान में इमरान खान की कैबिनेट में मंत्री

कि कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है। पाकिस्तान और कांग्रेस की साझेदारी का प्रवापरा हो गया है। यह दिखाता है कि देश के दुश्मन भारत में मजबूत नहीं बल्कि कमजोर सरकार चाहते हैं। उहाँने कहा, एक कमजोर सरकार जो 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के समय थी। वे एक ग्रेट सरकार चाहते हैं जो 2014 से पहले थी। लोकिन मोदी की मजबूत सरकार न तो चुकती है और न ही रुकती है। उहाँने कहा कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं है जब कांग्रेस सत्ता में थी, अब पाकिस्तान के आतंक के दायर पंक्ति हो गए हैं। मोदी ने कहा, यह आश्वस्त्री की बात नहीं है कि कांग्रेस अतीत में आतंक का व्योकि हम पहले से ही जानते हैं

कि कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है। पाकिस्तान के बांग्रेस की साझेदारी का प्रवापरा हो गया है। यह दिखाता है कि देश के दुश्मन भारत में मजबूत नहीं बल्कि कमजोर सरकार चाहते हैं। उहाँने कहा, एक कमजोर सरकार जो 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के समय थी। वे एक ग्रेट सरकार चाहते हैं जो 2014 से पहले थी। लोकिन मोदी की मजबूत सरकार न तो चुकती है और न ही रुकती है। उहाँने कहा कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं है जब कांग्रेस सत्ता में थी, अब पाकिस्तान के आतंक के दायर पंक्ति हो गए हैं। मोदी ने कहा, यह आश्वस्त्री की बात नहीं है कि कांग्रेस अतीत में आतंक का व्योकि हम पहले से ही जानते हैं

कि कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है। पाकिस्तान के बांग्रेस की साझेदारी का प्रवापरा हो गया है। यह दिखाता है कि देश के दुश्मन भारत में मजबूत नहीं बल्कि कमजोर सरकार चाहते हैं। उहाँने कहा, एक कमजोर सरकार जो 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के समय थी। वे एक ग्रेट सरकार चाहते हैं जो 2014 से पहले थी। लोकिन मोदी की मजबूत सरकार न तो चुकती है और न ही रुकती है। उहाँने कहा कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं है जब कांग्रेस सत्ता में थी, अब पाकिस्तान के आतंक के दायर पंक्ति हो गए हैं। मोदी ने कहा, यह आश्वस्त्री की बात नहीं है कि कांग्रेस अतीत में आतंक का व्योकि हम पहले से ही जानते हैं

कि कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है। पाकिस्तान के बांग्रेस की साझेदारी का प्रवापरा हो गया है। यह दिखाता है कि देश के दुश्मन भारत में मजबूत नहीं बल्कि कमजोर सरकार चाहते हैं। उहाँने कहा, एक कमजोर सरकार जो 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के समय थी। वे एक ग्रेट सरकार चाहते हैं जो 2014 से पहले थी। लोकिन मोदी की मजबूत सरकार न तो चुकती है और न ही रुकती है। उहाँने कहा कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं है जब कांग्रेस सत्ता में थी, अब पाकिस्तान के आतंक के दायर पंक्ति हो गए हैं। मोदी ने कहा, यह आश्वस्त्री की बात नहीं है कि कांग्रेस अतीत में आतंक का व्योकि हम पहले से ही जानते हैं

कि कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है। पाकिस्तान के बांग्रेस की साझेदारी का प्रवापरा हो गया है। यह दिखाता है कि देश के दुश्मन भारत में मजबूत नहीं बल्कि कमजोर सरकार चाहते हैं। उहाँने कहा, एक कमजोर सरकार जो 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के समय थी। वे एक ग्रेट सरकार चाहते हैं जो 2014 से पहले थी। लोकिन मोदी की मजबूत सरकार न तो चुकती है और न ही रुकती है। उहाँने कहा कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं है जब कांग्रेस सत्ता में थी, अब पाकिस्तान के आतंक के दायर पंक्ति हो गए हैं। मोदी ने कहा, यह आश्वस्त्री की बात नहीं है कि कांग्रेस अतीत में आतंक का व्योकि हम पहले से ही जानते हैं

कि कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है। पाकिस्तान के बांग्रेस की साझेदारी का प्रवापरा हो गया है। यह दिखाता है कि देश के दुश्मन भारत में मजबूत नहीं बल्कि कमजोर सरकार चाहते हैं। उहाँने कहा, एक कमजोर सरकार जो 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के समय थी। वे एक ग्रेट सरकार चाहते हैं जो 2014 से पहले थी। लोकिन मोदी की मजबूत सरकार न तो चुकती है और न ही रुकती है। उहाँने कहा कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं है जब कांग्रेस सत्ता में थी, अब पाकिस्तान के आतंक के दायर पंक्ति हो गए हैं। मोदी ने कहा, यह आश्वस्त्री की बात नहीं है कि कांग्रेस अतीत में आतंक का व्योकि हम पहले से ही जानते हैं

कि कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है। पाकिस्तान के बांग्रेस की साझेदारी का प्रवापरा हो गया है। यह दिखाता है कि देश के दुश्मन भारत में मजबूत नहीं बल्कि कमजोर सरकार चाहते हैं। उहाँने कहा, एक कमजोर सरकार जो 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के समय थी। वे एक ग्रेट सरकार चाहते हैं जो 2014 से पहले थी। लोकिन मोदी की मजबूत सरकार न तो चुकती है और न ही रुकती है। उहाँने कहा कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं है जब कांग्रेस सत्ता में थी, अब पाकिस्तान के आतंक के दायर पंक्ति हो गए हैं। मोदी ने कहा, यह आश्वस्त्री की बात नहीं है कि कांग्रेस अतीत में आतंक का व्योकि हम पहले से ही जानते हैं

कि कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है। पाकिस्तान के बांग्रेस की साझेदारी का प्रवापरा हो गया है। यह दिखाता है कि देश के दुश्मन भारत में मजबूत नहीं बल्कि कमजोर सरकार चाहते हैं। उहाँने कहा, एक कमजोर सरकार जो 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के समय थी। वे एक ग्रेट सरकार चाहते हैं जो 2014 से पहले थी। लोकिन मोदी की मजबूत सरकार न तो चुकती है और न ही रुकती है। उहाँने कहा कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं है जब कांग्रेस सत्ता में थी, अब पाकिस्तान के आतंक के दायर पंक्ति हो गए हैं। मोदी ने कहा, यह आश्वस्त्री की बात नहीं है कि कांग्रेस अतीत में आतंक का व्योकि हम पहले से ही जानते हैं

कि कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है। पाकिस्तान के बांग्रेस की साझेदारी का प्रवापरा हो गया है। यह दिखाता है कि देश के दुश्मन भारत में मजबूत नहीं बल्कि कमजोर सरकार चाहते हैं। उहाँने कहा, एक कम

कोरोना वैक्सीन पर राजनीति नहीं



संजय गोस्वामी

पहली और दूसरी खुराक प्राप्त करने के 48 घंटे बाद, 687 अभ्यास (पुण्य = 275; महिला = 412) में बुखार, शरीर में दर्द, ठंड लगना, मतली, मैलिगिया, सिरदर्द, अस्वस्थता, थकान की व्यापकता का आकलन किया गया और पहली खुराक की तुलना में दूसरी खुराक के प्रशासन के 48 घंटे बाद अन्य प्रणालीगत खुराक में

काफी गिरावट आई
अधिकांश प्रतिकूल घटनाओं
में साइड इफेक्ट की रिपोर्ट
दर <0.50% थी, जो सभी
पुरुष एवं महिला के लिए
वैक्सीन के लिए कोविशील्ड
सुरक्षित है। कोरोना कब
खत्म हो गया और इसपर
अभी भी राजनीति चालू है,
इस पर राजनीति नहीं करनी
चाहिए, क्योंकि ये आम लोग
के स्वास्थ्य से जुड़ा है
जानकारी के अमाव लोग
घबरा जाएंगे।

को रोना की कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी एस्ट्रजेनेका ने कोर्ट में माना है कि इस वैक्सीन से कुछ लोगों को दिल का दौरा और ब्रेन

स्ट्रोक का खतरा है। यह वही वैक्सीन है जिसका भारत में

बड़े पैमाने पर सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए उत्पादन किया गया था। एक निजी संस्थान द्वारा उत्पादित वैक्सीन को न केवल सरकार द्वारा प्रचारित किया गया, बल्कि इसे आईसीएमआर द्वारा प्रमाणित और सुरक्षित भी बताया गया। जबकि सभी जानते हैं कि वैक्सीन का ट्रायल बहुत जल्दबाजी में किया गया था, किलनिकल और अन्य परीक्षणों की लंबी और वर्षों-लंबी प्रक्रिया को कुछ महीनों और हफ्तों में यह कहकर संक्षेप में प्रस्तुत किया गया कि यह समय की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री ने स्वयं सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया और इसके एमडी अदार पूनावाला के साथ देश को वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने खुद भी टीका लगवाया और देशवासियों से भी टीका लगवाने की अपील की। इसके बाद कोवैक्सिन, कोरेवेक्स जैसी कई अन्य वैक्सीन भी आईं और लगाई गईं। सरकार ने इसे बड़े पैमाने पर खरीदा और जनता को मुफ्त में सप्लाई किया। पूरे देश में टीकाकरण शिविर आयोजित किये गये। वैक्सीन लेने के लिए लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा। वैक्सीन प्रमाणपत्र वितरित किए गए और कई सरकारी सेवाओं के लिए यह प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया। यह प्रमाणपत्र आज भी हम सभी के मोबाइल फोन या दराज में है।

माजूद है। ये सब हुए कई साल बात गए, कराना का कभी-कभी छोटी लहर की चर्चा के अलावा कोई बड़ी लहर नहीं आई है। ऐसा लगता है कि वैक्सीन का असर हुआ है। कोरोना के नए-नए वेरिएंट आते हैं और बिना कोई खास असर दिखाए वापस चले जाते हैं। पुराने वेरिएंट को वैक्सीन से खत्म कर दिया गया है और इम्यूनिटी बढ़ने से नए वेरिएंट को अपनी ताकत दिखाने और बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर, अचानक दिल का दौरा, हार्ट अरेस्ट और ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। आए दिन हमें ऐसी खबरें और वीडियो पढ़ने, देखने और सुनने को मिलते हैं। न केवल भारत में, बल्कि ब्रिटेन सहित अन्य देशों में भी, जहां कोविशील्ड का आविष्कार किया गया था। स्ट्रोजेनेका कंपनी ने इसे सबसे पहले कहां बनाया था और किन देशों से लाइसेंस या सहयोग लेकर अन्य देश और उनकी वैक्सीन कंपनियां इसका उत्पादन कर रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इनका सबसे बड़ा उत्पादक है और इसकी बनी वैक्सीन पूरी दुनिया में सप्लाई होती है। लेकिन अब एस्ट्रोजेनेका मुश्किल में है और उसकी परेशानी का साया सीरम इंस्टीट्यूट से लेकर भारत सरकार तक दिखाई दे रहा है। चूंकि इन दिनों भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं कोविशील्ड पर एस्ट्रोजेनेका के कबूलनामे से विपक्ष को

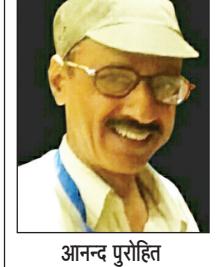


सरकार के खिलाफ नया हथियार मिल गया है। कोविशील्ड के बारे में खतरनाक तथ्य सामने आने से उन चिपक्षी दलों को भी नई ताकत मिलेगी जिनके नेताओं ने शुरूआत में इस वैक्सीन का मजाक उड़ाया था और इसे बीजेपी की वैक्सीन बताकर इसे लगावाने से इनकार कर दिया था। हालाँकि बाद में जनता के दबाव में उन्होंने वैक्सीन लगावा ली, लेकिन कई आम लोगों की तरह वैक्सीन को लेकर उनका सदैह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इनमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख का नाम प्रमुख है। उनकी पार्टी इस चुनाव में भारत गठबंधन का हिस्सा है। जब से एस्ट्रोजेनेका द्वारा अदालत में वैक्सीन की खामियों को स्वीकार करना मीडिया में उजागर हुआ है, जिस महिला की कथित तौर पर कोविशील्ड लेने के बाद मृत्यु हो गई, उसके माता-पिता ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ईंडिया (एसआईआई) के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला किया है, जिसके एक दिन बाद भारत में वैक्सीन बेचने वाली एस्ट्रोजेनेका ने अदालत में स्वीकार किया कि उनका कोविड शॉट एक दुर्लभ दुष्प्रभाव का कारण बन सकता है। एस्ट्रोजेनेका का कबूलनामा सामने आने के बाद अधिभावकों को न्याय की उम्मीद है। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने एक सम्मेलन बैठक में कहा, सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड के दुष्प्रभाव नगण्य से भी कम हैं। कोविड-19 एक घातक बीमारी है, और हम सभी को जीवन में बाद में अनावश्यक स्थितियों से बचने के लिए उचित साधारणी बरतनी चाहिए। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केरोना और कोविशील्ड को लेकर चचाओं से भर गए हैं। ऐसा लगता है मानों सबको अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया हो। कोई इसके लिए एस्ट्रोजेनेका और अदार पूनावाला को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई इसे चुनावी बांड चढ़ि और विदेश में कॉरपोरेट जगत के लालच से जोड़ रहा है। कोरोना महामारी

को लेकर अब भी लोगों में सदिह होने लगा है। वे पूछ रहे हैं कि क्या यह पश्चिमी अमीरों और शासकों की कोई सुनियोजित साजिश नहीं थी? जिसके तहत जनसंख्या को कम करने और फारम्सी, अस्पताल, बीमा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मरीन लर्निंग जैसे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के करोड़ों लोगों को गिनी पिंग बनाया गया और उनके जीवन और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया और इसके लिए चीन जिम्मेदार है। आपको यह जानना चाहिए कि किसी भी दवा का मानव के इलाज में प्रयोग करने से पहले क्लिनिकल परीक्षण किया जाता है वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्लिनिकल परीक्षण में नगण्य है सबसे पहले किसी रसायन जो कि टीके या दवा के लिए प्रयोग किया जाना है का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। यदि प्रयोगशाला में सफलता मिल जाती है, तो इसके बाद इसका प्रयोग छोटे जानवरों (जैसे चूहा, बिल्ली, आदि) पर किया जाता है। यदि इन पर भी प्रयोग सफल होता है तो यही प्रयोग विभिन्न जाति के बंदरों पर किया जाता है। इस परीक्षण में इस दवा के दुष्प्रिणाम तथा दवा के विषेलेपन का भी परीक्षण किया जाता है। यदि यहां तक सफलता मिल जाती है तो उसके बाद दवा नियंत्रक तथा अन्य नियामक एजेंसियों से मानव पर उपरोक्त दवा के परीक्षण की इजाजत मांगी जाती है। इस इजाजतनामे में मानव परीक्षण की जरूरत किस प्रकार का परीक्षण किया जायेगा, कौन-कौन शोधार्थी इसमें शामिल होंगे और किन-किन अस्पतालों के माध्यम से यह शोध किया जायेगा, इस सब का विवरण देना होता है। साथ ही हर चरण के परीक्षण के बाद सम्पूर्ण विवरण नई दवा या टीके का परीक्षण करने वाली कम्पनी को उक्त एजेंसी को देना होता है मानव परीक्षणों में हर दवा को तीन चरणों में गुजरना होता है पहला चरण क्लीनिकल ट्रायल होता है, जिसमें दवा की सुरक्षा तथा शरीर में

प्रतिराधक क्षमता तथा अलग-अलग मात्रा में दवा को खुराक देकर दवा की खुराक (डोज) निर्धारित की जाती है। पहले चरण के परीक्षण में 10 से 20 तक स्वस्थ मानवों की आवश्यकता होती है, तथा इस पूरी प्रक्रिया में दो वर्ष का समय लगता है। दूसरे चरण में यही प्रक्रिया 300 से ऊपर स्वस्थ मानवों में दोहरा कर परीक्षण किया जाता है। इस प्रक्रिया में भी दो वर्ष से ऊपर का समय लगता है तो सरे चरण में यह दवा उस बीमारी के हजारों रोगियों को दी जाती है, जिसे मर्ज के लिए यह दवा तैयार की गयी है। इस तीसरे चरण की खास बात यह है कि जितने मरीजों पर इस दवा का प्रयोग किया जा रहा है, उन्हें ही मरीजों पर लेसिबो (जो कि नमकीन पानी होता है) का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के बाद दोनों समूहों, जिन्हें दवा दी गयी है और जिन्हें लेसिबो दिया गया है, के नरीजों की तुलना की जाती है और सारी सूचना नियंत्रक एजेंसी देखती है कि क्या दवा में रोग को पूर्ण तथा समाप्त करने की क्षमता है या नहीं। साथ ही उसके मानवशरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी किया जाता है। फरवरी 2021 में, त्रिनिदाद और टोबैगो ने अपना राष्ट्रीय COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। वैक्सीन कार्यकर्ता ChAdOx1 ल्लाउझर्स-19 (ऑक्सफोर्ड-एस्ट्रजेनेका (कोविशील्ड, हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट, ऑफ ईंडिया, पुणे, भारत) प्राप्त करने वाले पहले समूह में थे, जो राष्ट्रीय स्तर पर पहली COVID-19 वैक्सीन उपलब्ध थी। आई बी एम कापोरेंशन, अमोन्क, एनवार्ड, यूएसए द्वारा किया गया परीक्षण में इस वैक्सीन की सुरक्षा जांच की गई, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त टीकाकरण के बाद रिपोर्ट की गई टीकाकरण के बाद सिस्टमगत और स्थानीय अध्ययन दस्तावेजों का एक क्रॉस-अनुभागीय अध्ययन, चिकित्सा और दस्तावेजीकरण दस्तावेज -19 से संबंधित इतिहास और पहले के अनुभव में दिए गए स्थानीय और सिस्टमगत अध्ययन से संबंधित डेटा के माध्यम से जांच किया गया था। इस परीक्षण की पहली और दूसरी खुराक प्राप्त करने के 48 घंटे बाद, 687 अभ्यास (पुरुष = 275; महिला = 412) में बुखार, शरीर में दर्द, ठंड लगना, मतली, मैलगिया, सिरदर्द, अस्वस्था, थकान की व्यापकता का आकलन किया गया और पहली खुराक की तुलना में दूसरी खुराक के प्रशासन के 48 घंटे बाद अन्य प्रणालीगत खुराक में काफी गिरावट आई अधिकांश प्रतिकूल घटनाओं में साइड इफेक्ट की रिपोर्ट दर <0.50% थी, जो सभी पुरुष एवं महिला के लिए वैक्सीन के लिए कोविशील्ड सुरक्षित है। कोरोना कब खत्म हो गया और इसपर अभी भी राजनीति चालू है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आम लोग के स्वास्थ्य से जुड़ा है जानकारी के अभाव लोग घबरा जाएं।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस : स्वतंत्रता के पहले सुधार जरूरी



आनन्द पुराहत

जवाबदेह बने संस्थाएं

जवाबदेह बने संस्थाएं

अदालत ने लोक सभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच जरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया और जांच एजेंसी से इसका जवाब मांगा गया। ने पांच सवाल पूछे और उनके जवाब लेकर आने का निर्देश दिया। सदस्यीय बैंच ने कहा कि स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायिक कार्यवाही के बिना देश को बहुत खतरा है। हुआ उसके संदर्भ में कार्यवाही कर सकते हैं। अदालत ने पूछा कि नंती मनीष सिसोदिया के लिए कहा कि पक्ष और विपक्ष कौन हैं। हमें बताएं कि केजरीवाल का मामला कहां है। क्या हां बहुत विस्तृत बनाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि जो व्यक्ति उसका पता लागाने के लिए मानक समान हो। केजरीवाल 20 शराब नीति घोटाले के मामले में न्यायिक हिरासत के तहत नीति तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल इस गिरफ्तारी से पहले निकल तोर पर कई मर्टबा दोहरा चुके थे कि मोदी सरकार लोकावाद के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली सरकार वे नीति ही जेल में हैं। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की विभिन्न राजनैतिक दलों के लिए चुनावी बनती जा रही है। यह दल की यह जिम्मेदारी है कि वह अन्य विपक्षी दलों के साथ भरा बर्ताव करने से बचे। दंड प्रक्रिया सहिता के अध्याय 5 वें विधान है, कोई भी गिरफ्तारी इसके अधीन ही होनी चाहिए। ल अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध बता रहे हैं। यह दल अलत नहीं है कि चुनाव के दरम्यान लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। नोटिस भी थमाए जा रहे हैं या छोपे तक डाले जा रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा जेनके उत्तर मिलने चाहिए। यह स्थिति लोकात्मिक व्यवस्था उचित नहीं कही जा सकती। बेशक, न्यायिक व्यवस्था अपनी निभा रही है। सार्वजनिक जीवन में रहने वाला कोई भी यदि किसी तरह के घोटाले में शामिल है तो उसे दंडित कर दिया जाना चाहिए। अदालतोंपर पहले ही लंबित मामलों का दबाव अदालतों हैं। अदालतोंपर पहले ही लंबित मामलों का दबाव अदालतोंपर आरोपियों को भाजपा में शामिल करने विट देने का काम कर स्पष्ट संकेत दे रही है। यह अपनी अदालत संदेश दे रहा है। बावजूद इसके अंतिम फैसला तो जननीय में है, जो मूकदर्शक जरूर है, लेकिन अपना निर्णय समय आ

पाँ च सौ सात सौ में प्रेस कार्ड और पांच सात लाख में अखबारों पत्र पत्रिकाओं द्वारा सम्मान की लॉलीपाप देने और मिलने की खबरें और सूचनाओं के बीच हम सब आज 3 मई को भारत में भी विश्व प्रेस दिवस मना रहे हैं। जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित करने के बाद विश्व प्रेस दिवस के रूप में ही जाना जाता है। प्रेस के हालात आज ये हैं कि, रील बनाने के लिए चौराहे पर नाचने वाली से लगाकर छोटे बड़े नेता अभिनेता या सोशल साइट्स के तथाकथित सेलिब्रिटी मतलब सीधे सफाशब्दों में कहें तो हर कोई ऐरा गैरा एक्स, वाय, झेड भी प्रेस (जिसके लिए वर्तमान में प्रचलित शब्द मिडिया) पर उंगली उठाता रहता है। चाहे उनका कृत्य गलत, अव्यावहारिक, असामाजिक या आपराधिक अथवा गैर जिम्मेदाराना ही क्यों न हों..... वे अपनी गलती अपनी कमी नहीं मान मीडिया को ही दोषी ठहराते हैं।..... आइना दिखाने के लिए उधर मीडिया में भी कुछेक जमीर वाले अभी भी हैं, जो उनका पुरजोर विरोध करते उनको ही नहीं जन जन को उनकी हैसियत बोलें

परन्तु धार धार व भा बहुत कम हात जा रह ह। आउनके लिए ही अत्यंत जरूरी है प्रेस स्वतंत्रता। भारत में प्रेस या कहें मीडिया एंव पत्रकारों की स्वतंत्रता अथवा आजादी भारतीय सर्विधान के अनुच्छेद-19 में भारतीयों को दिए गए अधिकारिकी की आजादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है। प्रेस की इसी आजादी को विश्व स्तर पर सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया जिसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में भी जान और मनाया जाता है। वैसे हम भारत के पत्रकार हमारा साल 16 नवंबर को हमारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे यहां पीसीआई की स्थापना जैसे हुई थी।

आज की पीढ़ी के जो पत्रकार हैं उनमें से शायद अधिकारिकों कोपीसीआई क्या है... यह ही पता न हो.... जिसके चलते वह भी यहां दिया जाना चाहिए है। हालांकि उनकी इस अपरिचितता के लिए इन पत्रकारों का कोई दोष नहीं है क्योंकि इन्हें बताया हो नहीं गया या इनकी मनोवृत्ति ऐसी कर दी कि इन्होंने जानना भी नहीं चाहा..... सबसे पहले और सबसे तेज के चक्रकर में ये यहां वहां से कोर्स कर कर के प्रेस का प्रतिनिधित्व करने पत्रकार बने या जैसा कि मैंने शुरूआत में कहा पांच सौ सात सौ में कार्ड लेकर फील्ड में आ गए.... पढ़ने जानने की, न लालसा रहना जिज्ञासा इसलिए नहीं जानते। खैर....

प्रेस स्वतंत्रता के संदर्भ में तो वर्तमान समय में दो स्तरीय स्थिति है.... एक जो लिखते हैं दूसरे जो लिखाते हैं..... सीधे सीधे कहे तो एक अखबार मालिक और दूसरे उनके कर्मी जिनमें संपादक, उप संपादक,

त प्रेस स्वतंत्रता किसके लिए ? क्या दाना के लिए ?
नये जमाने की प्रेस जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जा रहा उसकी बात करना तो बेमानी ही है.उसका कोई औचित्य हीं नहीं है... क्योंकि जब 1991 में युनेस्को ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का निर्णय लिया था तब इसका अस्तित्व ही नहीं था....और वर्तमान में भी नब्बे प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकारिता के मापदण्डों तक दस प्रतिशत भी नहीं पहुंच पाया है ।... ये तो बस बहसबाजी और बाईट मीडिया बन गया है । आलोचकों की मानें तो उनके अनुसार वहां... बाइट पत्रकारिता... होती है... बाईट ले ली बन गई रिपोर्ट हो गई पत्रकारिता.... तो 1991 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता की बात अखबारों के महेनजर ही कहीं गई थी । हालांकि अब इलेक्ट्रॉनिक के बाद एक और सोशल मीडिया भी प्रेस की जमाने में शामिल होने को तत्पर है... इसलिए प्रेस शब्द के आयाम का विस्तार तो जरूरी हो गया है । इसको पुनः परिभाषित भी करना होगा । सिर्फ अखबारों को लेकर प्रेस स्वतंत्रता की बात में तो पिछले वर्षों चर्चित एक व्यांग्यात्मक जुमला कि... जो छप कर बिकते थे अब बिक कर छोड़े बहुत कुछ कह गया है....संदर्भ सीमित था लेकिन अर्थ अनन्त है । ... हालांकि हकीकत यह भी है कि, कुछेक्षण ऐसे भी हैं....जो न छपकर बिकते हैं, न बिककर छपते हैं....बस चलते हैं....मतलब छपते ही नहीं तो और क्या... साल में दो चार छः बार भी छप गए तो छप गये नहीं तो चल तो रहे ही है ।..... सरकारी संस्थान जैसे मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग के प्रकाशन भी इसमें शामिल हैं... और ऐसे सैकड़े नहीं हजारों, लाखों हैं भारत में । इनमें से अधिकांश स्वयं सिद्ध नहीं होकर प्लांट किये गये हैं

प्राप्त क लए कुछ क्षत्र विशेष क सक्षमा द्वारा.... आर इन तथाकथित सक्षमों द्वारा ही पूर्ण जिम्मेदारी एवं ईमानदार से प्रकारिता के मानकों को निभाते प्रेस की मयार्दा और गरिमा को कायथ रखने वाले अखबारों को बांधने के जतन किए जा रहे हैं। चाहे नीतियों का हवाला देकर दबाव बनाते अथवा सुविधाओं के साथ प्रलोभन देकर.... मतलब साम दाम डण्ड भेद भरपूर चल रहा है प्रेस की आजादी को दबाने में। हालांकि ये तथाकथित सक्षम प्रेस के समर्थन से ही सक्षम बन पायें हैं, नहीं तो इनकी हैसियत कुछ भी नहीं थी.... और अब उस पर ही उंगली उठा उसे बांधने का प्रयास कर रहे... यह भूल कर की प्रेस का स्वरूप बहुत विराट है.... उसे किसी भी तरह के बंधन में बांधा जाना संभव नहीं है, परन्तु ये चंद प्रेस कों जयचंदी स्वभाव वालों से मिल उड़े प्रत्यक्ष या पोरेक्ष रूप से लाभान्वित कर या प्रलोभन देकर, उनके साथ अपना यह कुत्सित प्रयास कर रहे... इसलिए ही प्रेस स्वतंत्रता की जरूरत है.... लेकिन अभी उसके पहले प्रेस के इन लोभी जयचंदों की पहचान कर उन्हें हटाने की जरूरत है। भारत में इसके लिए ही शायद पीसीआई का गठन किया गया जिसकी स्थापना दिवस को हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा मैंने उपर बताया। पर पीसीआई अर्थात् प्रेस कॉसिल ऑफ ईंडिया भी अपनी स्थापना के उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया इसलिए वो भी परिवर्तनीय है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने के पहले प्रेस से दूषित लोभी जयचंदों को किनारे कर अखबार मालिकों और पत्रकारों को स्व आचार संहिता बना उसके अनुरूप आचरण सुधार की आवश्यकता है। दो शब्दों में कहूं तो स्वतंत्रता के पहले स्वच्छता।

भारत एवं कनाडा के रिश्ते खतरनाक मोड़ पर

खुद टूटो ने सावजनिक रूप से निजर हत्याकांड में भारत के शामिल होने का निराधार आरोप लगाया था। भारत के मांगने के बाद भी आज तक उनकी सरकार इस आरोप के पक्ष में कोई सबूत नहीं दे पाई है। जस्टिन टूटो ने आरोप लगाकर दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा कर दिया था। भारत ने आरोप के बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बात से कनाडा और भारत के संबंधों में खटास आ गया और दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की बजाय खतरनाक मोड़ पर पहुंच गये हैं।

रविवार के खालसा दिवस समारोह में न केवल

खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए बल्कि ऐसे बैन प्रदर्शित किए गए, जिनमें भारत-विरोध के त्रासद एवं राष्ट्र-विरोध के भ्रामक, झूटे एवं बेउनियाद आरोप थे अफसोस और चिंता की बात यह रही कि कनाडार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तो इन सब भारत-विरोधी घटनाओं को रोकें की या इन्हें गलत बताने की कोइ कोशिश की। इस पूरे मामले में ट्रूडो का व्यवहार आपत्तिजनक बना, दो देशों के बीच खटास घोलने वाला एवं राजनीतिक अपरिपक्वता का रहा। जिसे दोनों देशों के राजनयिक पैमाने पर उचित नहीं कह जा सकता। इस तरह कनाडा अपने देश के राजनीतिक जरूरतों के चलते भारत के साथ अपने रिश्ते इस मोड़ पर ले आया हैं, जहां उनके बीच विश्वास, भरोसे, आपसी सहयोग और संवाद के लिए हैं, जो इस देश के लिए अत्यधिक जरूरी हैं।

सरकार को प्रतिबद्धता में काइ आपात नहा है। सिव्व
समुदाय के मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा
करने के बायद यदि वहां की सरकार करती है तो
अच्छी बात है। भले ही कनाडा सरकार सिखों के
समुदायिक केंद्रों, गुरुद्वारा समेत पूजास्थलों की सुरक्षा
को और मजबूत करने के साथ भारत एवं कनाडा के
बीच उड़ानें और रुट बढ़ाने को लेकर भारत के साथ
नए समझौते करें, लेकिन इन स्थितियों के बीच
खालिस्तानी अलगाववाद को प्रोत्साहन देना भारत के
लिये असहनीय है। भारत बार-बार इस बात को दोहरा
रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस

नहीं आ रहा है। वह जिस तरह खालिस्तानी अतिवादियों को संरक्षण दे रही है, उसकी मिसाल यदि कहीं और मिलती है तो वह पाकिस्तान में। कनाडा अपने भारत विरोधी रवैये के कारण पाकिस्तान सरीखा बनना जा रहा है। कनाडा अपने हितैषी एवं पड़ोसी देशों से टूरियां बना रहा है। खालिस्तान समर्थन एवं प्रोत्साहन के चलते कनाडा में फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अपने देश के साथ दुनियाभर में वह आलोचकों के निशाने पर है। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों पर नियंत्रण रखने में कथित नाकामी के चलते टुडो को अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते जी-20 बैठक में उन्हें भारत और सदस्य देशों का हाईटंडाल्फ रिस्पांस मिला। भारत में खास अहमियत नहीं मिलने से खिसियाएं टुडो को कनाडा के मिडिया ने भी आड़े हाथ लिया है। टुडो सरकार पर भारत के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचाने और व्यापार वार्ता के बारे में अंदरे में खनन के आरोप भी लगे हैं। घरेलू राजनीतिक हितों के लिए टुडो भारत के साथ लड़ाई मोल लेकर अपने देश का भारी अर्थिक नुकसान कर रहे हैं। यह सर्वविदित है कि भारत अब दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। कनाडाई में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात और व्यापार में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का असर यहां की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। भारत की नाराजी बेवजह नहीं है, क्योंकि कनाडा भारत के विरोध में लगातार सक्रिय हैं, कनाडा ने ही किसानों के आंदोलन के समर्थन में अतिश्योक्तिपूर्ण सहयोग होने दिया।

राजा की उदासी

एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। एक न में चोरी करने का निश्चय लिया

हाकर उन्हाने राजमन्त्र में चारा करने का निश्चय किया। रात में वह वहाँ पहुँचे। सभी लोग सो रहे थे। सिपाहियों की नजरों से बचते हुए वह राजा के कक्ष तक पहुँच गए। स्वर्ण, रल, बहुमूल्य पात्र इधर-उधर पड़े थे। किंतु वे जो भी वस्तु उठाने का विचार करते, उनका शास्त्र ज्ञान उन्हें रोक देता। ब्राह्मण ने जैसे ही स्वर्ण राशि उठाने का विचार किया, मन में स्थित शास्त्र ने कहा- स्वर्ण चोर नरपाणी होता है। जो भी वे लेना चाहते, उसी की चोरी को पाप बताने वाले वाक्य उनकी स्मृति में जाग उठते। रात बीत गई पर वे चोरी नहीं कर पाए। सुबह पकड़े जाने के भय से ब्राह्मण राजा के पलांग के नीचे छिप गए। महाराज के जागने पर रानीयां व दासियां उनके अभिवादन हेतु प्रस्तुत हुईं। राजा भोज के मुंह से किसी श्वेत की तीन पर्कियां निकली। फिर अचानक वे रुक गए। शायद चौथी पर्कि उन्हें याद नहीं आ रही थी। विद्वान् ब्राह्मण से रहा नहीं गया। चौथी पर्कि उन्होंने पूर्ण की। महाराज चौंके और ब्राह्मण को बाहर निकलने को कहा। जब ब्राह्मण से भोज ने चोरी न करने का कारण पूछा तो वे बोले- राजन्- मेरा शास्त्र ज्ञान मुझे रोकता रहा। उसी ने मेरी धर्म रक्षा की। राजा बोले- सत्य है कि ज्ञान उचित-अनुचित का बोध करता है, जिसका धर्म संकट के क्षणों में उपयोग कर उचित राह पाई जा सकती है। राजा ने ब्राह्मण को प्रचुर धन देकर सदा के लिए उनकी निर्धनता दूर की दी।

क नाड़ी में रावराव का वहा का प्रधानमंत्री
जस्टिन टूटो की मौजूदगी में खालिसां दिवस
समारोह के दौरान खालिसां समर्थक नारे
लगाए जाने के बाद भारत सरकार जो सख्ती दिखाई है, वह आवश्यक एवं समयोचित कदम है। इस घटना पर भारत का चिंतित होना एवं कनाडा को चेताया जाना स्वाभाविक है। विदेश मंत्रालय में कनाडा के उप-उच्चायुक्त को तलब कर इस मामले में गहरी आपत्ति जताई गई है। कनाडा सरकार ने अपने राजनीतिक हितों के लिये अनेक बार भारत विरोधी घटनाओं में संदेहास्पद एवं विवादास्पद भूमिका का निर्वाह करते हुए अनर्तार्थीय संबंधों की मर्यादाओं को धूंधलाया है। कनाडा की धरती से खालिसानी समर्थक अलगाववाद, कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा दिया जाता रहा है। इस तरह की घटनाओं से कनाडा में अपराध का माहौल बना हुआ है। इससे कनाडा के नागरिकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। जिससे भारत में भी स्थितियां संकटपूर्ण बनी हैं। पिछले साल

